>

Title: Need to give subsidies to non-nationalised banks in the country.

श्री राजाराम पाल (अकबरपुर): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान, देश में आज किसानों की जो स्थिति है, उस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। देश के किसान कभी सूखे, कभी अतिवृष्टि से प्रभावित होते हैं। इस सदन मे लगातार चाहे इस पक्ष के लोग हों, चाहे उस पक्ष के लोग हों या सरकार हो, किसानों की बेहतरी के लिए बातें खूब करती है। पिछले समय यूपीए सरकार ने किसानों का बड़े पैमाने पर ऋण माफ किया था। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उस समय उन किसानों का ऋण माफ हुआ, जिन्होंने कर्जा नहीं दिया, यानी जो बेइमानी कर रहे थे। लेकिन जिन किसानों ने छोटा ऋण कहीं डीजल इंजन के लिए, कहीं भैंस के लिए और कहीं ट्रैक्टर के लिए लिया था, वे लगातार ऋण दे रहे थे। वे ईमानदार लोग थे, लेकिन उनको उसका कोई लाभ नहीं मिला।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकृत बैंक्स समस्त शहरों और कस्बों में हैं। लेकिन जो किसानों के हित में जो अराष्ट्रीकृत बैंक्स हैं, वे गांवों में हैं। भारत सरकार नैशनलाइज्ड बैंकों को तो सब्सिडी देती है लेकिन अराष्ट्रीयकृत बैंकों को कोई सब्सिडी नहीं मिलती, जिससे किसानों को उसका कोई लाभ नहीं मिलता।

अतः मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के वित्त मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि नैशनलाइज्ड बैंकों की तरह अराष्ट्रीयकृत बैंक्स भी छोटे किसानों को दीर्घकालीन ऋण दे सकें, इसके लिए उन्हें सब्सिडी प्रदान करने का काम करें। धन्यवाद।

सभापति महोदय : श्री कमल किशोर 'कमांडो' अपने आपको श्री राजा रामपाल जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।